



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 29, 2005 (SRAVANA 7, 1927 SAKA)

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 29 जुलाई, 2005

संख्या 22/52/2005-5 विद्युत.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में ऊर्जा के फलोत्पादक उपयोग तथा इसके संरक्षण के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :—

1. सौर जल तापीय प्रणाली का आझापक उपयोग

1. सौर जल तापीय प्रणाली का उपयोग भवनों के निम्नलिखित प्रवर्गों में आझापक होगा, अर्थात् :—

(क) उद्योगों में जहां प्रसंस्करण के लिये गर्म पानी अपेक्षित है।

(ख) हस्पताल और नर्सिंग होम जिसमें सरकारी हस्पताल भी शामिल हैं।

(ग) होटल, मोटल और समारोह हाल।

✓(घ) जेल बैरकें और कैन्टीनें।

(ङ) समूह आवास समितियों/हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्थापित हाउसिंग काम्प्लेक्स।

(च) नगरपालिका समितियों/निगमों तथा हुडा के सेक्टरों की सीमा के भीतर आने वाले 500 वर्ग गज तथा इससे अधिक आकार के भूखंड पर निर्मित सभी आवासीय भवन।

(छ) सभी सरकारी भवनों, आवासीय विद्यालयों, शैक्षणिक महाविद्यालयों, होस्टलों, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं, जिनका शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यटन काम्प्लेक्सों तथा विश्वविद्यालय इत्यादि।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा) विशिष्टियों के अनुसार श्रेष्ठ रूप से डिजाइन किये गये उत्तम गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करने के लिये राज्य में सौर जल तापीय प्रणालियों की आपूर्ति तथा स्थापना के लिये अनुमोदित स्रोत के रूप में कार्य करेगा।

वि. सभी सम्बन्धित विभाग जैसे गृह तथा सामाजिक न्याय विभाग, श्रमिकी विभाग, लोक निर्माण (भवन तथा आवास) विभाग, आवास बोर्ड, जन-स्वास्थ्य विभाग और मास्टरप्लान विभाग आदि को ज्ञात करी शक्ति से ही राज्य के भीतर सौर जल तापीय प्रणालियों का आझापक करने के लिये अपने विभाग/उप-विभागों को संशोधित करेंगे।

4. ये विभाग राज्य सरकार के निर्णय को मोनिटर करने तथा लागू करने की प्रगति अक्षय ऊर्जा विभाग को निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक आधार पर भेजने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर भी नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे।
2. सरकारी भवनों/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों/बोर्डों/निगमों में काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी०एफ०एल०) का आज्ञापक उपयोग
1. सरकारी सैक्टर/सरकारी सहायता प्राप्त सैक्टर/बोर्ड तथा निगमों/स्वायत्त निकायों में सभी नये निर्मित सभी नये भवनों/संस्थानों में इन्केंडेसेंट बल्बों के प्रयोग पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध किया जाता है।
 2. यह आज्ञापक होगा कि विद्यमान भवनों में खराब इन्केंडेसेंट बल्बों को जब बदला जाये तो केवल काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी०एफ०एल०) से ही बदला जायेगा।
 3. विद्युत उपयोगिता में, नये कनेक्शन अथवा नया लोड जारी/स्वीकृत करते समय पारम्परिक बल्ब के स्थान पर सी.एफ.एल. के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये इस आदेश के जारी होने के दो महीने के भीतर लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक उपांतरण करना होगा।
3. कृषि क्षेत्र में आई०एस०आई० मार्कड मोटर पम्प सैट, पावर कैपेसिटर, फुट/रिफ्लैक्स वाल्व का आज्ञापक उपयोग
1. सभी नये ट्यूबवैल कनेक्शनों के लिये आई०एस०आई० मार्कड पम्प सैट्स तथा एसैसरीज का उपयोग आज्ञापक होगा।
 2. राज्य में केवल आई०एस०आई० मार्कड पम्प सैट्स का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये इस आदेश के जारी होने के दो महीने के भीतर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ट्यूबवैल कनेक्शनों के लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक संशोधन करेगा।
4. ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन को बढ़ावा देना
1. सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले सभी नये भवनों में 30 जून, 2006 से ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिजाइन धारणा जिसमें अक्षय ऊर्जा तकनीक भी शामिल है, सम्मिलित करेंगे।
 2. वास्तुकला विभाग भविष्य में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले सभी भवनों में ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिजाइन धारणा को सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगा। वास्तुकला विभाग में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र निर्मित किये जाने वाले सभी नये भवनों की योजना/मानचित्रों की जांच करने तथा सुनिश्चित करने के लिये कि ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिजाइन धारणा की सभी विशेषताओं को इसमें सम्मिलित कर लिया गया के लिये एक समिति गठित की जायेगी।
 3. वास्तुकला विभाग इन उपायों के समन्वय तथा मोनिटरिंग के लिये एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा जो निदेशक, अक्षय ऊर्जा विभाग को इस बारे में प्रगति की सूचना देगा।
- इस मामले में पूर्व में जारी किये गये सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुये यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

एस० सी० चौधरी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Order

The 29th July, 2005

No. 22/52/05-5P.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Governor of Haryana hereby issues the following directions for efficient use of energy and its conservation in the State of Haryana, namely :—

1. Mandatory use of Solar Water Heating Systems

1. The use of solar water heating systems will be mandatory in the following categories of buildings, namely :—
- (i) Industries where hot water is required for processing,
 - (ii) Hospitals and Nursing homes including Government Hospitals.

- (iii) Hotels, Motels and Banquet halls.
- (iv) Jail Barracks, Canteens.
- (v) Housing Complexes set up by Group Housing Societies/Housing Boards.
- (vi) All residential buildings built on a plot of size 500 square yards and above falling within the limits of municipal committees/corporations and Haryana Urban Development Authority sectors.
- (vii) All Government buildings, Residential Schools, Educational Colleges, Hostels, Technical/Vocational Education Institutes, District Institutes of Education and Training, Tourism Complexes and Universities etc.

2. Haryana Renewable Energy Development Agency will act as an approved source for supply and installation of solar water heating systems in the State to ensure the installation of optimally designed quality systems as per the specifications.

3. All the line departments like Town and Country Planning Department, Urban Development Department, Public Works Department (Building and Roads), Housing Board, Public Health Department and Architecture Department will amend their rules/bye-laws within a period of two months from the date of issue of this order to make the use of solar water heating systems mandatory.

4. These departments will also designate a district and a state level nodal officer to monitor and report the progress of enforcement of the State Government decisions to the Department of Renewable Energy, Haryana on Quarterly basis in the prescribed format.

2. Mandatory use of Compact Fluorescent Lamp (CFL) in Government Buildings/Government Aided Institutions/Boards/Corporations

1. The use of incandescent lamps in all new buildings/institutions constructed in Government sector/ Government Aided sector/Board and Corporation/Autonomous bodies is banned with immediate effect.

2. It will be mandatory that in existing buildings the defective incandescent lamps when replaced, would be replaced by only compact fluorescent lamps (CFL).

3. Power utilities will affect necessary modification in the load demand notices within two months time from the date of issue of this order to promote the use of Compact Fluorescent Lamps instead of conventional bulbs while releasing/sanctioning new connections/loads.

3. Mandatory use of ISI marked Motor pump sets, Power capacitor, Foot/Reflex valves in Agriculture Sector

1. For all new tubewell connections, the use of ISI marked pump sets and accessories will be mandatory.

2. Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam/Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam will make the amendments in the load demand notices for tubewell connections within two months time from the date of issue of this order to ensure use of only ISI marked pumps in the State.

4. Promotion of Energy Efficient Building Design

1. All the new buildings to be constructed in the Government/Government Aided sector will incorporate energy efficient building design concepts including Renewable Energy Technologies with effect from 30th June, 2006.

2. The Architecture Department will ensure the incorporation of energy efficient building design concepts in all buildings to be constructed in future in the Government/Government Aided sector. A committee shall be formed in the Architecture Department to examine all new building plans/drawings to be constructed in the Government/Government Aided sector to ensure that all the features of the energy efficient building design concepts, have been incorporated in these.

3. The Architecture Department will designate a nodal officer for coordination and monitoring of these measures who will report the progress in this regard to the Director, Renewable Energy Department, Haryana.

THE ABOVE ORDER SUPERSEDES ALL PREVIOUS ORDERS IN THIS MATTER AND COME INTO FORCE WITH IMMEDIATE EFFECT.

S. C. CHAUDHARY,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Renewable Energy Department

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 31st October, 2005]

HARYANA GOVERNMENT
RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 31st October, 2005

No. 22/52/2005-5P(RE).—The Government of Haryana has issued a comprehensive notification *vide* Haryana Government Gazette (extraordinary) No. 22/52/2005-5P, dated 29th July, 2005 for adoption of various energy conservation measures namely, mandatory use of solar water heating systems, compact flourescent lamp (CFL) in Government buildings/Government Aided Institutions/Boards/Corporations, Use of ISI marked motor pump sets and accessories and promotion of energy efficient building design in Government/Government Aided Sector.

In order to monitor the implementation of above said energy conservation measures as well as of the Energy Conservation Act, 2001, the Governor of Haryana is pleased to constitute the following State Level Monitoring Committee :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Chief Secretary, Haryana | Chairman |
| 2. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Revenue Department | Member |
| 3. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Agriculture Department | Member |
| 4. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Public Works and Architecture Department | Member |
| 5. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Cooperation Department | Member |
| 6. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Health Department | Member |
| 7. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Urban Development Department | Member |
| 8. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Power Department | Member |
| 9. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Education Department | Member |
| 10. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Renewable Energy Department | Member |
| 11. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Panchayats and Rural Development Department | Member |
| 12. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Industries Department | Member |
| 13. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department | Member |
| 14. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Public Relations Department | Member |
| 15. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Environment Department | Member |
| 16. Director, RE/HAREDA | Member Secretary/ |

The committee will undertake periodic review of the implementation of various energy conservation measures as stipulated in the above-referred notification and Energy Conservation Act, 2001.

S. C. CHOUDHARY,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Renewable Energy Department.

सोलर गीजर इस्तेमाल करें

बिजली की बचत के साथ-साथ
पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करें।



प्रमुख विशेषताएँ

- ◆ होटलों, डेयरियों, जलपान गृहों, अस्पतालों, उद्योगों एवं घरों में 60-80° सेंटीग्रेड तक गर्म पानी के उपयोग के लिए उपयुक्त।
- ◆ कम से कम 100 ली. प्रतिदिन से शुरू कर के किसी भी क्षमता के सिस्टम बनाए जा सकते हैं।
- ◆ साल के 320 धूप वाले दिनों में काम कर सकता है।
- ◆ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सपैशीफिकेशन के अनुसार बनाए जाते हैं अतः भरोसेमन्द क्वालिटी।
- ◆ सिस्टम में दिन भर गर्म किया गया पानी ऊष्मारोधी गर्म पानी के टैंक में जमा होता है जो शाम को अथवा अगले दिन सुबह इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
- ◆ एक सौ लीटर के सिस्टम की कीमत लगभग 22000 रुपये है।
- ◆ केवल एक बार का खर्च, बार-2 कोई खर्चा नहीं
- ◆ सौ लीटर के सिस्टम से प्रति वर्ष लगभग 2200 यूनिट बिजली बचाई जा सकती है।
- ◆ सिस्टम की लागत इस्तेमाल और बचत किए गए ईंधन के अनुसार 2 से 5 वर्षों में वसूल।
- ◆ पर्यावरण का मित्र एवं प्रदूषण रहित।
- ◆ एक सौ लीटर के सिस्टम से सालाना 1.5 टन CO₂ के निकलने पर रोक।
- ◆ राष्ट्रीयकृत बैंकों से 2 से 5% की दर पर आसान ऋण उपलब्ध।
- ◆ हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित सप्लायरों का पैनल।
- ◆ हरेडा की देखरेख में सिस्टम लगवाने की व्यवस्था।

हरेडा - स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आंदोलन में अग्रणी

